



2026:

AHC:58528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2012 सन् 2026

विकास जायसवाल

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता

: शिखर अवस्थी

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री शिखर अवस्थी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 474 भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(2), 345(3), 347(1), 61(2) और आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत, थाना नोएडा सेक्टर-63, जनपद गौतम बुद्ध नगर में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम गिरफ्तार सह-आरोपी कुलदीप सिंह और रोहताश कुमार के संस्वीकृति कथन में सामने आया है। यह भी बताया गया है कि जाली क्यूआर कोड वाली शराब की कुछ बोतलें बरामद हुई हैं। आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक उस शराब की दुकान का मालिक है जहाँ से जाली क्यूआर कोड वाली शराब की बोतलें बरामद हुई हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उत्तर में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक दुकान का मालिक नहीं है और उसने सह-आरोपियों को उन लोगों से मिलवाया था जो जाली क्यूआर कोड बना सकते हैं।

6. गिरफ्तार सह-आरोपियों, अर्थात्, कुलदीप सिंह और रोहताश कुमार के संस्वीकृति कथन में आवेदक का नाम सामने आया है। कहा जाता है कि आवेदक ने सह-आरोपियों को उन लोगों से मिलवाया था जो जाली क्यूआर कोड बना सकते हैं।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक-विकास जायसवाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ, अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार

सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"